RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 135
दि. 14.09.2025, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

'मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा रत्न', इंफाल में बोले पीएम मोदी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का ये दौरान कई मायनों में खास है। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंच चुके हैं। मणिपुर में दो साल पहले हिंसा भड़कने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है।

पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में शांति आए स्थिरता आए, यहां के लोगों के हित सुरक्षित रहें, जो कैंपो में रहने को मजबूर हैं, उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7 हजार नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी घोषित किया है।

आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों-करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बनाएंगे।

प्रधानमंत्री इंफाल में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है और यहां कनेक्टिविटी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कों की कमी के कारण आपको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मैं उन्हें अच्छी तरह समझता हूँ। इसीलिए, 2014 से, मैंने मणिपुर की कनेक्टिविटी को लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया है और इसके लिए भारत सरकार ने दो स्तरों पर काम किया है। पहला, हमने मणिपुर में सड़क और रेलवे पर बजट बढ़ाया। दूसरा, हमने गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रयास किए... पिछले कुछ वर्षों में, मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,700 करोड़ रुपये खर्च किए गए। नए राजमार्गों के निर्माण पर 8,700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने निशाना साधा है।

आरएमएल स्थापना दिवसः सीएम योगी ने डॉक्टरों को किया सम्मानित, बोले- हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार

लखनऊ (जीएनएस)।

लखनऊ में डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर मरीज के साथ डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा हो। हर मरीज को अच्छी सुविधा मिले।

राजधानी लखनऊ में शनिवार को डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का पांचवा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा शामिल हुए।

इस मौके पर सीएम योगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों के लिए काफी अहम होता है। गरीब परिवारों के प्रति आपकी संवेदना होनी चाहिए। अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर मिल जाए। वार्ड बॉय उनकी मदद करें।

लोहिया संस्थान का स्थापना दिवस, सीएम योगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को किया सम्मानित।

उन्होंने कहा कि यदि किसी गरीब परिवार के किसी व्यक्ति की दुखद मौत हो जाती है, तो संस्थान के वाहन से शव उसके घर तक पहुंचा दें। हमारे पास वाहन नहीं है तो संस्थान एक वाहन खरीद लें। निजी एंबुलेंस जो मरीजों को निजी अस्पताल ले जाती हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। पेशेवर ब्लड डोनेशन करने वाले लोग मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। इस पर भी रोक लगे।

सीएम ने आगे कहा कि लोगों ने सोशल मीडिया को नजरअंदाज किया। विकास किस तरह बाधित हो जाता है। ये हमने पड़ोसी देश में देखा। आज के युग के अनुरूप हमें हर क्षेत्र में खुद को तैयार करना होगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान पीएचसी, सीएचसी में आरोग्य मेले लगेंगे। आरएमएल को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए।

तमाम घुमंतू जातियां अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखतीं। हमें उन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए।

जमीन मिलने पर होगा विस्तार

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोहिया संस्थान के विस्तार के लिए दूरदर्शन से बात चल रही है। वो जमीन मिलने से यहां का विस्तार हो सकेगा। यह जमीन संस्थान के पास ही उपलब्ध है।

सुशासन के 4 वर्ष : गुजरात के 32,200 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना का लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही गुजरात सरकार

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दिसंबर 2024 में शुरू की थी मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत बच्चों को दिया जाता है सुखडी, चना चाट, मिक्स दलहन, मिलेट का अल्पाहार

गांधीनगर, 13 सितंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाले जाने के आज 13 सितंबर 2025 को 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। सुशासन के इन 4 वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू हुई गुजरात की विकास यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। उनके दृढ़ नेतृत्व में गुजरात ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शुरू हुई लोक कल्याणकारी योजनाओं ने राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, जो शिक्षा के साथ पोषण के सर्वग्राही दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई थी।

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना : 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है कैलोरी-प्रोटीनयुक्त अल्पाहार

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रपटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने 11 दिसंबर 2024 को 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' की शुरूआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुपोषित गुजरात मिशन अंतर्गत सरकारी एवं अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को पीएम पोषण योजना अंतर्गत दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन के उपरांत पौष्टिक आहार देना सुनिश्चित करना है।

पीएम पोषण योजनांतर्गत समाविष्ट किए गए सभी विद्यालयों में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थी 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' अंतर्गत नियमित लाभ लेते हैं। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत औसत 200 किलो कैलोरी तथा 6 ग्राम प्रोटीन से युक्त पौष्टिक अल्पाहार विद्यार्थियों को दिया जाता है।

फलावदा मजार तोड़फोड़ मामले में सीसीटीवी से खंगाले जा रहे आरोपी, किसने दिया घटना को अंजाम?

(जीएनएस)।

यूपी के मेरठ के फलावदा कस्बे में गुरुवार की रात को एक घटना ने स्थानीय लोगों को हिला दिया। शरारती तत्वों ने मोहम्मद बब्बल शाह की मजार समेत छह मजारें तोड़ दीं। सुबह उठने के बाद जब लोग वहां पहुंचे तो मजार टूटा था। वहां पर बिखरी ईंटों और क्षतिग्रस्त मजारों को देखकर गुस्से में आ गए।

स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले की जानकारी मिलने के बाद आसपास की बस्ती से काफी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया गया लेकिन लोग आक्रोश जताने लगे। उसके बाद वहां पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। त्यप्रकाश, एसपी देहात राकेश मिश्रा और सीओ सरधना आशुतोष कुमार भी मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने टूटी मजारों की मरम्मत और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। उसके बाद मजार की मरम्मत का काम शुरू हुआ तो लोग शांत हुए।

हिंदू समुदाय के लोग भी चढ़ाते हैं चादर

बताया जा रहा है फलावदा कस्बा स्थित काले सिंह मंदिर मार्ग पर कब्रिस्तान में मोहम्मद बब्बल शाह की मजार के साथ कई अन्य मजारें भी हैं। दोनों समुदाय यहां चादर चढ़ाते हैं।

इन्हीं मजारों को गुरुवार रात शरारती तत्वों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया।

सुबह उठने के बाद सूफी निजामुद्दीन और पड़ोसी खेत स्वामी जुनैद जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मजारों के चारों ओर ईंटें बिखरी हुई थीं। उनके द्वारा आसपास के लोगों को जानकारी दी गई। मजार तोड़े जाने की जानकारी मिलते ही वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए।

उसके बाद वहां पहुंचे स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को फोन करके इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

हालांकि प्रभारी के समझाने के बाद भी मौके पर मौजूद लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस दौरान लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करते नजर आए। भीड़ बढ़ती देख वहां पर अन्य थानों से भी फोर्स बुलाई गई।

अधिकारियों के समझाने पर शांत हुए ग्रामीण

प्रभारी द्वारा इसकी सूचना अधिकारियों को दी गई। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम, एसपी देहात और सीओ भी मौके पर पहुंचे उसके बाद अधिकारियों द्वारा भरोसा दिया गया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

मोदी सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बंपर निवेश, ₹1,500 करोड़ खर्च करने की तैयारी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया अब तेजी से अपना रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दशक में यह तकनीक पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट से लेकर पढ़ाई और दूसरे सेक्टर में हावी हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि भारत का आने वाला समय टेक्नोलॉजी और रिसर्च का है। भारत सरकार अगले हफ्ते इंडिया एआई मिशन के तहत ₹1,500 करोड़ की राशि के दूसरे राउंड के लाभार्थियों की घोषणा करने जा रही है। यह मिशन देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

रतलाम में सीएम मोहन यादव का 'ऑन द स्पॉट' एक्शनः फरियादी की फरियाद सुनी, धोखेबाज को पकड़ने के दिए आदेश

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे जनता के दुख-दर्द को समझने वाले और त्वरित फैसले लेने वाले नेता हैं। रतलाम में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक पीड़ित युवक की फरियाद सुनी और तत्काल कार्रवाई का आदेश देकर न केवल उसका भरोसा जीता, बल्कि उसे गले लगाकर भावनात्मक समर्थन भी दिया।

इस मामले में एक ऑटोमोबाइल कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप है, जिसने युवक को पुरानी गाड़ी बेचकर लाखों रुपये का चूना लगाया। सीएम के इस संवेदनशील और त्वरित एक्शन की तारीफ न केवल स्थानीय लोगों, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हो रही है।

रतलाम में शुक्रवार को आयोजित एक जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनता की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान पूनम चंद, एक स्थानीय निवासी, अपनी शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा। पूनम चंद ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसने एक ऑटोमोबाइल कंपनी से 8 लाख 32 हजार रुपये में फाइनेंस पर एक फोर-व्हीलर खरीदा था। उसने अब तक 9 लाख 86 हजार रुपये का भुगतान भी कर दिया, लेकिन कंपनी ने धोखे से उसे एक साल पुरानी गाड़ी की बॉडी बदलकर बेच दी। पूनम चंद ने कहा, "मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने मेहनत की कमाई लगाई, लेकिन कंपनी ने मुझे ठग लिया।"

पूनम चंद की बात सुनकर सीएम डॉ. मोहन यादव भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, "जिसने भी यह फ्रॉड किया है, उसे तत्काल गिरफ्तार करें। धोखाधड़ी के इस मामले में धारा 420 (IPC) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी को हवालात में डालें।" इसके बाद, उन्होंने पूनम चंद से कुछ देर बात की, उसका दुख समझा, और उसे गले लगाकर आश्वासन दिया कि उसे जल्द इंसाफ मिलेगा।

सीएम डॉ. मोहन यादव का यह अंदाज वहां मौजूद लोगों के लिए एक भावनात्मक क्षण था। पूनम चंद, जो अपनी शिकायत लेकर निराशा में था, को सीएम का यह व्यवहार देखकर नई उम्मीद मिली।

उन्होंने कहा, "मैंने सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री मेरी बात इतनी गंभीरता से सुनेंगे। उन्होंने मुझे गले लगाया और भरोसा दिया कि मेरा नुकसान नहीं होगा।"

एनडीए मे किसे कितनी सीटें, उम्मीदवार कैसे तय होंगे? पटना पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने जमाई फील्डिंग

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल अब जमीन पर साफ नजर आने लगी है। शनिवार (13 सितंबर) को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और उनके दौरे के साथ ही पूरे सियासी माहौल में एक नई सरगर्मी दिखी। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और फिर वे सीधे निजी कार्यक्रमों और चुनावी बैठकों में जुट गए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जेपी नड्डा का ये दौरा इतना अहम क्यों है।

नड्डा का पटना दौरा क्यों अहम?

जेपी नड्डा का यह बिहार दौरा महज एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि "मिशन 2025" की नींव रखने वाला कदम माना जा रहा है। वे यहां संगठन को धार देने, सीट बंटवारे की रणनीति तय करने और उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा करने आए हैं। रविन्द्र भवन में उन्होंने "मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान" की शुरूआत की। इसका मकसद है चुनावी संदेश को घर-घर तक पहुंचाना और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक बीजेपी का माहौल बनाना।

नड्डा जैसे ही पटना पहुंचे, वैसे ही एक और मोर्चा गर्म हो गया। 8,000 से ज्यादा बर्खास्त संविदा कर्मचारियों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है-"समान काम, समान वेतन और 60 साल तक नौकरी।" पिछले 29 दिनों से वे गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे और शनिवार को उनका गुस्सा बीजेपी दफ्तर के बाहर फूट पड़ा।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को जाम के बीच गाड़ी से उतरकर पैदल ऑफिस जाना पड़ा। हालात को देखते हुए नड्डा की अहम चुनावी बैठक का स्थल बदलना पड़ा और अब यह स्टेट गेस्ट हाउस में हो रही है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि NDA में सीटों का बंटवारा आखिर कैसे होगा।

राजस्थान में मानसून ने लिया ब्रेक, अगले पांच दिन तापमान बढ़ेगा, महसूस होगा गर्मी का असर

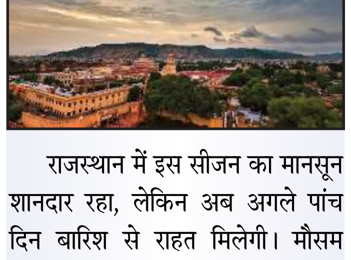

राजस्थान में इस सीजन का मानसून शानदार रहा, लेकिन अब अगले पांच दिन बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान बढ़ रहा है और कई शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया है।

बीते चौबीस घंटों में तापमान में एक से दो डिग्री तक वृद्धि हुई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे शहरों में दिन का पारा रिकॉर्ड स्तर पर है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिन उमस और गर्मी का असर महसूस होगा।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

अपर महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती स्टेशन एवं इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो साबरमती का निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने 13 सितम्बर 2025 को अहमदाबाद मंडल के साबरमती रेलवे स्टेशन तथा इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो (कळऊ) साबरमती का व्यापक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप कुमार ने साबरमती स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यो के तहत नवनिर्मित यात्री सुविधाओं जैसे कि कोनकोर्स हॉल, वेटिंग एरिया, टिकट बुकिंग विंडो, यात्रियों के लिए अलग-अलग एंट्री और एग्जिट पथ, लिफ्ट तथा स्टेशन पर उपलब्ध अन्य सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सभी प्लेटफार्मों पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निमार्णाधीन फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर्स, कवर शेड आदि विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

इस अवसर पर उप मुख्य परियोजना प्रबंधक (अहमदाबाद) श्री अनंत कुमार ने साबरमती स्टेशन पर जारी पुनर्विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी अपर महाप्रबंधक को दी तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

अपर महाप्रबंधक ने साबरमती स्थित इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो (कळऊ) का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोचों के रखरखाव एवं परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया। विशेष रूप से उन्होंने वंदे भारत ट्रेनसेट के लिए विकसित किए जा रहे मेंटेनेंस डिपो की कार्य प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सेवाओं के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिक तकनीकों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में लगातार विभिन्न ठोस कदम उठाए जा रहे है। यात्रियों को अधिकतम सुविधा एवं विश्वस्तरीय सेवाएं प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक साथ मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस का सहरसा तक विस्तार

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 19483/19484 अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस को सहरसा तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 19483 अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस अहमदाबाद से निर्धारित समय 00.35 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 22.55 बजे सहरसा पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 19484 सहरसा-अहमदाबाद एक्सप्रेस 14 सितंबर 2025 से सहरसा से 16.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 11.55 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

बरौनी से सहरसा के बीच यह ट्रेन बेगूसराय, खगड़िया, मानसी और सिमरी बख्तियारपुर स्टेशनों पर रुकेगी।

अहमदाबाद से बरौनी के बीच इस ट्रेन के आगमन/प्रस्थान समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ट्रेनों के ठहराव और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

11 साल के लिव इन रिलेशन का ऐसा खौफनाक अंत

हत्या की वजह जानकर चौंक जाएंगे

उत्तराखंड के हरिद्वार में एक व्यक्ति ने अपने लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों 11 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों की आठ साल की एक बेटी भी है। हत्या की वजह सोशल मीडिया में सक्रियता और महिला का किसी ओर से संपर्क होने का शक बताया जा रहा है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भभूतावाला बाग का है। जहां जिला अस्पताल के ड्राइवर ने अपनी लिव-इन पार्टनर की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपी युवक मुकेश पुजारी पिछले करीब 11 साल से शिवलोक कॉलोनी में रहने वाली पिंकी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। जो कि ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। दोनों की आठ साल की एक बेटी भी है। मुकेश की पहली शादी भी हो चुकी है और उसकी पहली पत्नी से दो जवान बेटे हैं, जो अलग रहते हैं।

महिला 11 साल पहले मुकेश के लिए अपने दो बच्चे और पति को छोड़कर आई थी। जिसके बाद से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थीं। मुकेश ने अपनी लिव इन पार्टनर के लिए पास में ब्यूटी पॉर्लर भी खुलवाकर दिया। 11 साल तक सबकुछ सही चल रहा था,लेकिन अब पिंकी की सोशल मीडिया पर सक्रियता और रील बनाना मुकेश को पंसद नहीं थी।

शक और विवाद की वजह से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ जिसका खौफनाक अंत हो गया। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात करीब एक बजे मुकेश ने पिंकी को फोन कर बाहर बुलाया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात बढ़ने लगी। बाद में मुकेश ने अपनी पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में मुकेश ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।

'अपने बायोडाटा में ये लिखिए', विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीमकोर्ट का आया अहम फैसला

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल एनयूजेएस विश्वविद्यालय के कुलपति निर्मल कांति चक्रवर्ती के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, न्यायालय ये फैसला चुनाते हुए बड़ा आदेश भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अहम टिप् पणी करते हुए कहा कि कुलपति के रिज्यूम में ये केस और आरोप लिखा जाए। इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पीड़िता ने 26 दिसंबर 2023 को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि यौन उत्पीड़न अप्रैल 2019 में हुआ था। स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) ने शिकायत को समय-बाधित मानते हुए खारिज कर दिया था, क्योंकि शिकायतकर्ता ने तीन महीने की निर्धारित सीमा और छह महीने की विस्तारित सीमा दोनों का उल्लंघन किया था।

पीड़िता के अनुसार, कुलपति चक्रवर्ती ने जुलाई 2019 में विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला। दो महीने बाद, 8 सितंबर को, उन्होंने पीड़िता को अपने कार्यालय में बुलाया और डिनर के लिए अनुरोध किया। उन्होंने महिला के हाथ को छुआ,

जिससे वह असहज महसूस कर रही थी। इसके बाद महिला चुपचाप वहां से चली गई।

अक्टूबर 2019 में, कुलपति ने उसे दोबारा अपने कार्यालय में बुलाया और डिनर के प्रस्ताव के बारे में पूछा। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा कि वह केवल पेशेवर संबंध बनाए रखना चाहती है। इसके बाद, कुलपति ने कथित तौर पर यौन संबंध बनाने की मांग की और उसे धमकी दी।

अक्टूबर 2019 में, पीड़िता की पदोन्नति रोक दी गई, जिसे अंततः 2 अप्रैल 2022 को कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी। अप्रैल 2023 में, कुलपति ने पीड़िता को एक रिसॉर्ट में आने को कहा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद, उसे करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई।

29 अगस्त 2023 को, सेंटर ऑफ फाइनेंशियल, रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस स्टडीज (CFRGS) से महिला को निदेशक पद से हटा दिया गया। उसी समय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस (NFCG) से प्राप्त अनुदान के दुरुपयोग के मामले में पीड़िता के खिलाफ जांच शुरू की गई। कार्यकारी परिषद ने एनयूजेएस को 1 लाख रुपये तुरंत वापस करने का आदेश दिया। पीड़िता ने ई-मेल के माध्यम से कार्यकारी परिषद और कुलपति से उत्पीड़न और बदले की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निदेशक पद से हटाना यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एनएफसीजी की स्वतंत्र रिपोर्ट पर आधारित था। इस कार्रवाई को पिछली कथित घटनाओं से जोड़ा नहीं जाएगा।

पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के पीछे क्या है मजबूरी? पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आया बड़ा बयान

(जीएनएस)।

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सियासत गरमा गई है। विपक्षी पार्टियां जहां इस मैच के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाने के बाद कई पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने इस मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं।

सोशल ममीडिया पर भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने इस मैच का विरोध करते हुए सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने इस मैच को लेकर सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इतने विरोध के बावजूद आखिर ये मैच भारत के लिए खेलना क् यों जरूरी है? पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसकी वजह बताई है।

पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के पीछे क् या है मजबूरी?

अनुराग ठाकुर ने बताया कि एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित टूनार्मेंट में ऐसे मुकाबलों से बचा नहीं जा सकता। यदि कोई देश ऐसे टूनार्मेंट में खेलने से मना करता है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ सकता है या उसे अंक गंवाने पड़ सकते हैं।

अगर भारत नहीं खेलता पाक के साथ मैच तो क्या होगा?

अनुराग ठाकुर ने न्यूज एजेंसी अठक द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में बताया, "जब एसीसी या आईसीसी के टूनार्मेंट होते हैं, तो देशों के लिए खेलना अनिवार्य हो जाता है।

एमाजान इंजीनियर ने किया फिलिस्तीन का समर्थन, कंपनी का एक्शन बना ग्लोबल चर्चा का मुद्दा

(जीएनएस)।

ई-कॉमर्स कंपनी Amazo»»f ने फिलिस्तीनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अहमद शाहरूर को सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह उनके द्वारा इजराइली सरकार और Amazon के बीच हुए समझौते Project Nimbus का विरोध बताया जा रहा है।

शाहरूर का कहना है कि यह प्रोजेक्ट इजराइल को एआई और डेटा सेंटर जैसी सुविधाएं देता है, जिससे फिलिस्तीनियों पर निगरानी और दमन आसान हो जाता है। वहीं, Amazon ने आरोप लगाया कि शाहरूर ने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया है। यह मामला न सिर्फ टेक कंपनियों की नीतियों बल्कि फिलिस्तीनी कर्मचारियों की आवाज दबाए जाने पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है।

क्यों किया गया अहमद शाहरूर को सस्पेंड?

अहमद शाहरूर पिछले तीन सालों से Amazon की Whole Foods डिवीजन में सिएटल ऑफिस से काम कर रहे थे। उन्होंने Slack चैनलों और एक ओपन लेटर के जरिए Project Nimbus का विरोध किया था। शाहरूर का आरोप है कि यह प्रोजेक्ट इजराइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर जैसी

आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराता है, जिसका इस्तेमाल फिलिस्तीनी लोगों पर नियंत्रण और निगरानी के लिए किया जा सकता है। विरोध के तुरंत बाद Amazon ने उन्हें नोटिस भेजा और सस्पेंड कर दिया।

प्रोजेक्ट निम्बस और विवाद

Project Nimbus 2021 में Google और Amazon की साझेदारी में शुरू हुआ था। इसका मकसद इजराइली सरकार को उन्नत तकनीकी सेवाएं देना है। लेकिन मानवाधिकार संगठनों और कर्मचारियों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से फिलिस्तीनियों के खिलाफ सैन्य और निगरानी गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। अहमद शाहरूर और अन्य कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की डील टेक कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करती है।

फिलिस्तीनी कर्मचारियों की मुश्किलें

शाहरूर ने कहा कि Amazon लगातार फिलिस्तीनियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से राय रखने से रोक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि फ्रांस में भी एक कर्मचारी को सोशल मीडिया पर इजराइल की आलोचना करने के चलते नौकरी से निकाला गया। शाहरूर के अनुसार यह सिर्फ उनकी नौकरी नहीं बल्कि फिलिस्तीनी पहचान और अधिकारों को दबाने की कोशिश है।

टेक कंपनियों में बढ़ते विरोध की लहर

Amazon ही नहीं, Microsoft में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। कुछ समय पहले कंपनी ने चार कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया था क्योंकि उन्होंने इजराइल को दी जा रही तकनीकी मदद का विरोध किया था। यह घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि बड़ी टेक कंपनियों में इजराइल से जुड़ी डील्स के खिलाफ कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की शुरूआत, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन, क्या हैं पात्रता

(जीएनएस)।

शहर में सपनों का घर तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवास निर्माण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत 2.75 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने दलाली से बचने की अपील की है। आवासविहीन शहरी आबादी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना चलाई जा रही है। जिसके लिए नगर निगम ने आवेदन आमंत्रित किए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की शुरूआत सितंबर 2024 में की गई थी और यह अगले पांच वर्षों के लिए यह योजना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के

परिवारों को आवास निर्माण या खरीद में केंद्रीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत 2.25 लाख की सहायता केंद्र सरकार और 50 हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों को दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत खाली भूखंड पर मकान बनाने वाले या कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, एकल महिला, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और सफाई कर्मियों जैसे वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है योजना पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित है।

योजना में वही परिवार पात्र होंगे जिनमें पति-पत्नी और अविवाहित बेटे-बेटियां शामिल हैं और जिनके पास किसी भी राज्य या शहर में पक्का आवास नहीं है।

जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में किसी अन्य आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया हो, इसके अलावा, लाभार्थी को 01 सितंबर 2024 से पहले नगर निगम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत बने मकान महिला मुखिया के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण

आवेदक का बैंक खाता विवरण (जो आधार से जुड़ा हो)

तीन लाख रुपये से कम आय का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा

भूमि संबंधी दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के अंतर्गत)

स्व-घोषित शपथ पत्र

सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग? इस पूरी घटना पर कलेक्टर ने बता दी पूरी सच्चाई

(जीएनएस)।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार सुबह गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट में एक बड़े हादसे से बच गए। जानकारी के अनुसार, वे हॉट एयर बैलून की सवारी करने पहुंचे थे। तेज हवा और अचानक लगी आग ने हालात तनावपूर्ण बना दिए।

गनीमत रही कि सुरक्षा गार्ड और स्टाफ ने तत्काल स्थिति को काबू में कर लिया और किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सीएम मोहन यादव हिंगलाज रिसॉर्ट में रात बिताने के बाद सुबह हॉट एयर बैलून की सवारी करने पहुंचे। उस समय हवा की रफ्तार लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसकी वजह से बैलून उड़ान नहीं भर सका। इसी दौरान बैलून के निचले हिस्से में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आग बुझाई और ट्रॉली को संभाला, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे। एमपी के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक की खबरें भ्रामक। हॉट एयर बैलून में आग जलने को बताया सुरक्षा में चूक। मंदसौर कलेक्टर ने किया

इंकार।

सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा

आग लगने के बाद स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी, लेकिन स्टाफ की त्वरित कार्रवाई से सीएम समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि बैलून उड़ान भरने से पहले ही आग लगी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

मुख्यमंत्री ने बोटिंग और बाइक बोट का भी आनंद लिया

इससे पहले मुख्यमंत्री ने चंबल नदी की सैर की और बोटिंग का आनंद लिया। उनके साथ सांसद सुधीर गुप्ता, गरोठ विधायक चंदर सिसोदिया, कमिश्नर आशीष सिंह, आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर अदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाइक बोट की सवारी भी की और पानी की लहरों पर उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि यह गतिविधियां पर्यटन को बढ़ावा देंगी और प्रदेश की प्राकृतिक धरोहरों को देखने का अवसर प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने सफारी जीप से एयर बैलून स्थल का रुख किया। रास्ते में उन्होंने टेंट सिटी का निरीक्षण किया और वहां की पर्यटन सुविधाओं की जानकारी ली।

प्रशासन ने क्या कहा?

अब इस पूरी घटना के बाद कलेक्टर अदिति गर्ग ने कहा कि एयर बैलून की पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री केवल एयर बैलून देखने पहुंचे थे और किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक नहीं हुई।

यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट पहुंचे थे। तेज हवा और अचानक आग ने एक पल के लिए अफरा-तफरी मचा दी, लेकिन सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से स्थिति संभाल ली गई।

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले गंभीर का सख्त मैसेज, कोच ने बताई टीम मीटिंग के अंदर की बात

(जीएनएस)।

एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर यानी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच हर बार की तरह सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। इस बार यह भिड़ंत और भी संवेदनशील हो गई है क्योंकि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। उसी घटना के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान किसी खेल में आमने-सामने आ रहे हैं।

फैंस और पूर्व खिलाड़ी इस मैच को लेकर बेहद नाराज हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और केदार जाधव ने भी साफ शब्दों में कहा है कि इस हालात में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना सही नहीं है। हालांकि बीसीसीआई ने सरकार के निर्देश पर फैसला लिया कि द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी, लेकिन बहु-देशीय टूनार्मेंटों में भारत को खेलना ही पड़ेगा।

भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशाटे ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खिलाड़ी हालात को समझते हैं और वे मैदान पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

गंभीर आपराधिक आरोपों से घिरे राजनीतिज्ञों के लिये अब मुश्किल हुई

राजनीति से अपराधियों की सफाई ही लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। सवाल है कि क्या हमारे राजनीतिक दल और नेता इस सच्चाई को स्वीकार कर अपनी राजनीति को स्वच्छ बनाने का साहस दिखाएंगे, ऐसा तत्काल तो संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त करने की बात सिर्फ छलावा है। लोकतंत्र की शुचिता के लिए बढ़ता खतरा अपराधियों का राजनीतिकरण! एक ताजा रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति की हकीकत को बेपर्दा कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश के 643 मंत्रियों में से 302 (47%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 174 मंत्री गंभीर अपराधों जैसे हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपित हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की बात लंबे अरसे से हो रही है। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रयासों के बावजूद देश की राजनीति में अपराधीकरण कम होने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि राजनीति में अपराधी तत्वों की घुसपैठ कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पर यह बढ़ा है, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की ताजा रिपोर्ट इस सच्चाई को बयान करती है कि देश के लगभग आधे मंत्री ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। अब सवाल यह आता है कि जब कानून बनाने और उसे लागू कराने वाले ही दागी होंगे तो क्या वे सचमुच न्याय और निष्पक्ष शासन की रक्षा कर पाएंगे? एडीआर के एक विश्लेषण के अनुसार देश के लगभग 47 प्रतिशत मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जिनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा उन तीन विधेयकों को संसद में पेश किए जाने के कुछ दिन बाद आई है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। हाल ही में एडीआर ने 27 राज्य विधानसभाओं, तीन केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 643 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया और पाया कि 302 मंत्रियों, यानी कुल मंत्रियों के 47 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 302 मंत्रियों में से 174 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण के अनुसार भाजपा के 336 मंत्रियों में से 136 यानी 40 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 88 यानी 26 प्रतिशत पर गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस शासित चार राज्यों में पाटा के 45 मंत्रियों यानी 74 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 18 यानी 30 प्रतिशत के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं। द्रमुक के 31 मंत्रियों में से 27 यानी लगभग 87 प्रतिशत पर आपराधिक आरोप हैं, जबकि 14 यानी 45 प्रतिशत पर गंभीर मामले दर्ज हैं। तृणमूल कांग्रेस के भी 40 में से 13 मंत्रियों यानी 33 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 यानी 20 प्रतिशत पर गंभीर आरोप हैं। तेलुगु देशम पाटा (तेदेपा) का अनुपात सबसे ज्यादा है, जिसके 23 में से 22 मंत्रियों यानी 96 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 13 यानी 57 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप के 16 में से 11 यानी 69 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पांच यानी 31 प्रतिशत पर गंभीर मामले दर्ज हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 29 यानी 40 प्रतिशत ने अपने हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके विपरीत हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों ने अपने खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने की सूचना दी है। देखा जाए तो सभी पार्टियों में दागी नेता है, जबकि देश के सभी दल अपराध मुक्त राजनीति की बात करते हैं।

आंकड़ों को देखने के बाद साफ है कि हिंदुस्तान की सियासत आज जिस रास्ते पर चल रही है वह भ्रष्टाचार और अपराध से लबालब है। आपको पता है चुनाव में बढ़ता धनबल, बाहुबल और अपराधी करण लोकतंत्र को अंदर ही अंदर खा रहा है। जब कानून के निर्माता और रखवाले ही अपराध में सने होंगे तो उनसे वैसे उम्मीद की जा सकती है कि लोकतंत्र को स्वस्थ रख सकेंगे। पहले तो बिहार और उत्तर प्रदेश को ही आपराधिक राजनीति का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले दो-तीन दशकों से सभी राज्यों में ऐसी प्रवृत्ति के नेताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। आज नेताओं का उद्देश्य चुनाव जीतकर देश सेवा करना नहीं, बल्कि सत्ता हासिल कर हुकूमत करना है। कालेजियम व्यवस्था के रहते हमारी न्यायपालिका को भी पूर्ण पवित्र नहीं कहा जा सकता है। राजनीति का अपराधीकरण केवल संसद और विधानसभाओं को ही प्रभावित नहीं करता, वरन समाज और लोकतंत्र की जड़ें खोखली कर देता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव जीतने के लिए दागी उम्मीदवारों को टिकट देने में कोई परहेज नहीं किया जाता है। 'हमाम में सभी नंगे हैं' की तर्ज पर सभी राजनीतिक पार्टियों की गोद में ऐसे अनेक नेताओं की किलकारियां गूंजती हैं, जो अपराध में आकंठ डूबे हैं। चुनावों में अपराधीकरण बढ़ने का बड़ा कारण चुनावी व्यवस्था की खामियां हैं। चुनाव लड़ने के लिए अपार धन की जरूरत होती है, और यही धनबल राजनीति में अपराधियों के लिए रास्ता खोल देता है। अपराध से अर्जित धन चुनावी मैदान में खर्च होता है और उसके बदले सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलता है। बाहुबल और धनबल के सहारे चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधि जनता के प्रति कम और अपने अपराधी गिरोह के प्रति ज्यादा जवाबदेह हो जाते हैं। हालांकि इस दिशा में पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। शीर्ष न्यायालय बार-बार कह चुका है कि गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल वोट बैंक की मजबूरी में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से बाज नहीं आते हैं। राजनीति में अपराध को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से बाहर कर सके। साथ ही चुनावी खर्च की सीमा का कड़ाई से पालन और पारदर्शी फंडिंग व्यवस्था भी जरूरी है। कानून से ज्यादा जरूरी है राजनीतिक दलों का आत्मसंयम और नैतिकता। यदि दल अपराधियों को टिकट न दें तो यह समस्या स्वतः कम हो जाएगी। लेकिन आज की राजनीति में सत्ता की लालसा इतनी प्रबल है कि दल अपराधियों को भी सिर-आंखों पर बिठाने से हिचकते नहीं। जब तक दल खुद यह संकल्प नहीं लेंगे कि वे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को ही आगे बढ़ाएंगे, तब तक लोकतंत्र में शुचिता की उम्मीद करना व्यर्थ है। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए आदर्श माना जाता है, लेकिन यह तभी टिकेगा जब इसकी जड़ें मजबूत हों। अपराधीकरण और भ्रष्टाचार लोकतंत्र की नींव को खोखला कर रहे हैं। यदि आज ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कल जनता का भरोसा इस व्यवस्था से पूरी तरह उठ जाएगा। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि यह जनता के प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिकता का प्रतीक है। राजनीति से अपराधियों की सफाई ही लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। सवाल है कि क्या हमारे राजनीतिक दल और नेता इस सच्चाई को स्वीकार कर अपनी राजनीति को स्वच्छ बनाने का साहस दिखाएंगे, ऐसा तत्काल तो संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त करने की बात सिर्फ छलावा है।

रूस पर प्रतिबंध लगाने और चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने के लिए ट्रम्प ने चली चाल! नाटो पर अब बनाया दबाव

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने रूस पर मॉस्को की पकड़ तोड़ने के लिए चीन पर 50-100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि इन प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो अमेरिकी संसाधनों की बबार्दी होगी।

शनिवार को ट्रंप ने नाटो देशों पर रूस से तेल खरीद बंद करने और उस पर प्रतिबंध लगाने का दबाव डाला। उन्होंने यूक्रेन युद्ध समाप्त होने तक चीन पर 50-100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का सुझाव दिया।

ट्रंप की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसमें भारतीय तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल था, लेकिन चीन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नाटो सदस्यों और "दुनिया" को संबोधित एक पत्र में, ट्रंप ने लिखा, "मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूँ, जब सभी नाटो राष्ट्र सहमत हों और ऐसा करना शुरू करें, और जब सभी नाटो राष्ट्र रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। जैसा कि आप जानते हैं, जीतने के लिए नाटो की प्रतिबद्धता 100 प्रतिशत से बहुत कम रही है, और कुछ लोगों द्वारा रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली है! यह रूस पर आपकी बातचीत की स्थिति और मोलभाव की शक्ति को बहुत कमजोर करता है।"

ट्रंप ने गठबंधन से सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह किया और कहा कि नाटो सदस्य प्रतिबंधों पर सहमत होते ही वे "जाने" के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "वैसे भी, जब आप तैयार हों, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बस बताइए कब?" अमेरिकी

राष्ट्रपति ने यह भी प्रस्ताव दिया कि नाटो मॉस्को पर चीन के प्रभाव को कमजोर करने के लिए चीन पर भारी टैरिफ लगाए।

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि यह, साथ ही नाटो द्वारा एक समूह के रूप में चीन पर 50% से 100% टैरिफ लगाना, जिसे रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा, इस घातक, लेकिन बेतुके युद्ध को समाप्त करने में भी बहुत मदद करेगा। चीन का रूस पर एक मजबूत नियंत्रण और यहाँ तक कि पकड़ भी है, और ये शक्तिशाली टैरिफ उस पकड़ को तोड़ देंगे।"

अमेरिकी टैरिफ की धमकियों के बीच चीन ने रूस के साथ अपने ऊर्जा व्यापार का बचाव किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने ब्लूमबर्ग न्यूज को एक ब्रीफिंग में कहा, "चीन के लिए दुनिया भर के सभी देशों, जिसमें रूस भी शामिल है, के साथ सामान्य आर्थिक, व्यापार और ऊर्जा सहयोग करना वैध और कानूनी है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार उचित ऊर्जा सुरक्षा उपाय अपनाना जारी रखेंगे।"

ट्रंप ने नाटो को चेतावनी दी कि उनके प्रस्तावों पर कार्रवाई करने में विफल रहने से अमेरिकी संसाधनों की बबार्दी होगी। उन्होंने कहा, "अगर नाटो ऐसा करता है, जैसा मैं कहता हूँ, तो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, और उन सभी जानें बच जाएँगी! यदि नहीं, तो आप मेरा समय, और संयुक्त राज्य अमेरिका का समय, ऊर्जा और धन बर्बाद कर रहे हैं।"

एक दिन पहले, शुक्रवार को ब्रिटेन ने रूस से संबंधित प्रतिबंधों का एक नया पैकेज लॉन्च किया था, जिसमें रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों, साथ ही रूसी हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और विस्फोटकों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को लक्षित किया गया था।

यह आ'ान तब आया है जब ट्रंप ने नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात को लेकर भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। उन्होंने रूसी कच्चे तेल खरीदने वाले देशों, जिसमें शीर्ष खरीदार चीन और भारत भी शामिल हैं, पर द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी भी दी है, यदि युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती है।

क्या रद्द होगा वक्फ संशोधन अधिनियम? सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (15 सितंबर 2025) को वक्फ (संशोधन) इस नए कानून को अंतरिम रूप से निलंबित किया जाए या नहीं।

अधिनियम 2025 पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने जा रहा है। यह फैसला इस बात पर होगा कि क्या

गौरतलब है कि अदालत ने इस मामले में मई महीने में तीन दिन तक सुनवाई के बाद 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुल 21 याचिकाओं के जरिए इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

6 जून 2025 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण यूएमईईडी नामक डिजिटल पोर्टल पर छह महीने के भीतर कराने का आदेश दिया। इसका विरोध करते हुए याचिकाकताओं ने तर्क दिया कि इससे समुदाय पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

22 अगस्त को सुनवाई के दौरान जब याचिकाकताओं ने इस अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की, तो चीफ जस्टिस भुषण आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने साफ कहा कि चूंकि फैसला पहले से सुरक्षित है, इसलिए अब अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता।

याचिकाकताओं के ने क्या दिए तर्क?

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि 1954 से लेकर 2025 तक राज्य सरकारों और केंद्र का दायित्व था कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और पहचान की जाए। लेकिन सरकार की इस असफलता का खामियाजा अब समुदाय को भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है। अन्य याचिकाकताओं ने यह भी आपत्ति जताई कि नए कानून में वक्फ की स्थापना केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो कम से कम पांच साल से मुसलमान हो। उनका कहना था कि अन्य धर्मों की धार्मिक संपत्तियों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

केंद्र सरकार ने क्या कहा?

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि 2013 के संशोधन में किसी भी व्यक्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार देना एक अवधारणात्मक गलती थी। उन्होंने सवाल किया कि "वक्फ, जो पूरी तरह से इस्लामिक अवधारणा है, उसे गैर-मुस्लिम कैसे घोषित कर सकते हैं?"

इसके अलावा, उन्होंने अनुसूचित जनजातियों की जमीन पर वक्फ बनाने पर प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए है। हालांकि, पीठ ने इस तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि धर्म एक है, परंपराएं अलग हो सकती हैं।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की परंपरा सौ साल से अधिक पुरानी है। 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम से लेकर 1954 और उसके बाद के कानूनों तक, संपत्तियों की सूची और पंजीकरण को हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है। सोमवार को आने वाला यह फैसला न केवल वक्फ अधिनियम 2025 के भविष्य का निर्धारण करेगा बल्कि देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के मुद्दे पर भी दूरगामी प्रभाव डालेगा।

'उत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम हिन्दी'

भाषा की सर्वोत्तम उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है हिन्दी। हिन्दी की सहजता, सरलता, सरसता अद्वितीय है। प्रत्येक भाषा अपने आप में निपुण है, परंतु शब्दों की सुंदरता से आलोकित एवं सुशोभित हिन्दी भाषा अप्रतिम है। यह सत्य है कि भाषा विहीन व्यक्ति कभी भी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। भाषा ही हमारी उन्नति को पल्लवित, पुष्पित एवं चहुं ओर हमारे विकास को प्रसारित करती है। हिन्दी में विचारों के प्रवाह का अद्वितीय सौंदर्य विद्यमान है।

भाषा की अस्मिता का गौरव गुणगान है हिन्दी।

वेदनाओं एवं भावनाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति है हिन्दी।

समस्त भाषाओं को कदमताल देती उन्नत स्वरूप है हिन्दी।

सूक्ष्म, अमूर्त और जटिल अनुभवों का सहज सम्प्रेषण है हिन्दी।

अंग्रेजी हमने सहर्ष नहीं अपनाई थी, वह तो अंग्रेजो द्वारा हम पर थोपी गई थी। आज भी हम उसी जंजीर के गुलाम बने हुए है। भाषा की गुलामी की जंजीरों और बेड़ियों को तोड़कर हमें एकमत होना होगा। हिन्दी की अनुभूति कितनी अनुपम है यह उसमें निहित शब्दों का चयन प्रदर्शित करता है। हिन्दी तो वह है जो नैतिकता को सहेजती है। निर्मल गंगा सा भाव एवं प्रवाह उत्पन्न करती है। साहित्य को शिरोधार्य बनाती है। कवियों की ललकार और भाषा की बयार से उन्नति के सोपान को छूती है। भारत माता के प्रति अतुलनीय प्यार के अनुपम स्वर में व्याप्त है हिन्दी। हिन्दी भाषा का अनोखा दर्पण है। हिन्दी में भावों को मुख से मन तक समर्पित करने की उत्कृष्टता है।

भाषा की धुरी पर स्वाभिमान का आविर्भाव है हिन्दी। जब भी साहित्य का सृजन किया जाता है तो हर पात्र को जीवंत बनाकर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है हिन्दी। नए भारत में उन्नति और उत्थान के भाव को संवाहित करने का सामर्थ्य हिन्दी में ही है। यदि भाषा की होली के उत्सव को हिन्दी से सजाया जाए, औजपूर्ण हिन्दी के माधुर्य को मुख पर गुनगुनाया जाए, अलंकारों के रंगों से अभिव्यक्ति को नित-नवीन बनाया जाए और हिन्दी के प्रयोग से काव्य रचना के स्वर से हृदय को आलोकित किया जाए तो मन रूपी हृदय में उन्नति, उत्साह और उमंग के रंग को बिखरने का अनुपम सौन्दर्य हिन्दी में ही है। राष्ट्र की उन्नति में माँ की ममता के आशीर्वाद का रूप हिन्दी प्रकट करती है।

जीवन की समग्रता का अंकन है हिन्दी।

सांकेतिकता, प्रतिकात्मकता का उत्कृष्ट आयाम है हिन्दी।

मानवीय भावों का यथार्थ चित्रण है हिन्दी।

अभिनव मूल्यों के उद्घाटन की चेतना है हिन्दी।

वर्तमान समय में अंग्रेजी ही आधुनिकता का आधार मानी जा रही है। भावी पीढ़ी की दृष्टि में हिन्दी का महत्व न्यून है। कितनी बड़ी विडम्बना है इस देश और समाज की कि हम अपने पूर्वजों की धरोहर जो हमें अनायास और सहजता से मिली है उसे ठुकरा रहे है और अंग्रेजों द्वारा परोसी गई भाषा को ग्रहण कर उसका उन्नयन कर रहे है। भाषा हमारी संस्कृति की अस्मिता और धरोहर है। यह केवल संवाद का माध्यम ही नहीं अपितु विचारों, भावनाओं एवं संवेदनाओं का उद्वेग है। उन्नति के सोपान की ओर कदम बढ़ाते वक्त अंग्रेजी को भी सीखना चाहिए, परंतु हिन्दी के प्रति अपने प्रेम को भी जीवंत एवं निष्ठावान रखना होगा। भाषा के विभिन्न स्वरूपों में अंग्रेजी भी ज्ञान का ही एक रूप है, परंतु मातृ भाषा की कीमत पर हिन्दी को तुच्छ समझकर अंग्रेजी को आत्मसात करना उचित नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में प्रेम एवं स्नेह का सरल रूप हैं हिन्दी। हिन्दी अवधि, ब्रज, भोजपुरी इत्यादि सभी भाषाओं को समन्वय प्रदान करती है।

आज हमारे संस्कारों में अंग्रेजी घुल रही है। आज का युवा वर्ग अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना ही अपनी उच्चता का मानक मान रहा है। वह मनोभावों की भाषा समझने में असमर्थ है। अंग्रेजी बोलना समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक बनती जा रही है। समाज में उन्नति के मापदंड हेतु अंग्रेजी बोलना चयनित किया जा रहा है। मातृ भाषा भारत वासियों के बीच हीनता का अनुभव कर रही है। यह हमारी भाषा की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह है। भाषा की दुर्बलता राष्ट्र की अभिव्यक्ति में न्यूनता को प्रदर्शित करती है। वह राष्ट्र की पहचान को क्षीण करती है। वैश्विक युग में सफलता के शीर्ष पर पहुँचते वक्त प्रत्येक भाषा को अपनाना होगा, पर हिन्दी के प्रति प्रेम में कृपणता परिलक्षित न करें। हिन्दी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय संकलन है हमें इसे सहेजना होगा। आत्मविश्वास से एवं पूर्ण निष्ठावान होकर इसे आत्मसात करना होगा। यह आत्मा के स्वरों का बोध है। हिन्दी सांस्कृतिक स्वरूप का एक ओजस रूप है। हिन्दी तो सर्वगुण सम्पन्न भाषा का दर्पण है। यह भाषा राष्ट्र के प्रति समर्पण है। एक स्वर और एक नाद से हम भारत वासियों को हिन्दी भाषा में अभिव्यक्ति को स्वीकारना चाहिए।

कथ्य के अनुरूप रचना संकलन को पहचान देती है हिन्दी।

पात्रो-चरित्रों के उद्घाटन का सजीव रूप है हिन्दी।

संवाद एवं प्रसंगानुकूल रोचकता की जनक है हिन्दी।

डॉ. रीना कहती, भाषा के सौन्दर्य की अनुपम छटा बिखेरती है हिन्दी।

डॉ. रीना रवि मालपानी (कवयित्री एवं लेखिका)

प्रेषकः डॉ. रीना रवि मालपानी

9039551172

अरशद वारसी और अक्षय कुमार ने दोस्तों में करवाई लड़ाई, नीलम ने उगला जहर?

(जीएनएस)।

'बिग बॉस 19' दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इसके हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिल रहा है, और प्रोमो वीडियो ने तो फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। हाल ही में, शो में 'जॉली एलएलबी 3' की टीम ने कोर्ट रूम ड्रामा पेश किया, जिसमें घर के सदस्यों को कठघरे में खड़ा किया गया।

कलर्स की तरफ से एक प्रोमो शेयर किया गया। जिसमें अरशद और अक्षय एक खेल खेलते हैं। तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद कठघरे में थीं, जबकि नीलम गिरी उनके बीच खड़ी होकर सवालों के जवाब दे रही थीं। इस दौरान अक्षय कुमार ने नीलम से पूछा कि तान्या और कुनिका में से कौन ज्यादा दोषी है और किसे पीठ पीछे बात करने की आदत है। इस पर नीलम ने तान्या का नाम लिया।

हीं'ल्लि'' श१ वस्रंशि

जब अक्षय ने तान्या से उनके जवाब के बारे में पूछा, तो तान्या ने कहा, "मैं जाती थी तो दोस्ती का फायदा उठाते हुए ये कह सकती थी कि मैं नाराज हो जाऊंगी अगर तू उनके पास गई तो।" नीलम गिरी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "मुझे कल ऐसा लगा है तान्या मित्तल को लेकर कि ये मुझे धोखा दे सकती हैं।"

कोर्ट रूम ड्रामा में अक्षय कुमार ने नीलम से यह भी पूछा कि क्या तान्या उन्हें पीठ में छुरा घोंप सकती हैं, जिस पर नीलम ने 'हां' में जवाब दिया। इसके बाद, जब उनसे पूछा गया कि कौन अपनी बात से अक्सर पलट जाता है, तो नीलम गिरी ने कहा, "मुझे ऐसा लगता है ना सर कि मैम को कई बार खुद भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या-क्या बोला है?" नीलम की बातें सुनकर अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वह बच-बचाकर जवाब दे रही हैं। उन्होंने पूछा, "डर लगता है क्या आपको उनसे, सपने में आएंगी वो आपके, नागिन बनकर डस लेंगी।" रिपोर्ट्स की माने तो इस हफ्ते नतालिया घर से बेघर हो रही हैं।

एशिया कप की ट्रॉफी सिर्फ इंडिया की होगी', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले बॉलीवुड एक्टर ने जीता दिल

(जीएनएस)।

: भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर यानी रविवार को बड़ा मुकाबला खेला जाना है। बॉलीवुड एक्टर जायेद खान ने एशिया कप 2025 में होने वाले मैचों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टीम इंडिया की फॉर्म को देखते हुए दावा किया है कि इस बार खिताब कोई और टीम नहीं, बल्कि भारत ही जीतेगा।

जायेद खान ने टीम इंडिया को लेकर क्या कहा

जायेद खान ने मीडिया से

बातचीत में कहा कि इंडिया एक जबरदस्त टीम है और मुझे पूरा यकीन है कि यह टूनामेंट भारत ही जीतेगा। इंडिया सबको मैदान से बाहर कर देगा। टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरूआत शानदार अंदाज में की है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को केवल 9 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत एशिया कप में खिताब का सबसे बड़ा दावेदार है।

राजनीतिक तनाव पर पूछा गया सवाल

जायेद खान से जब भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर राजनीतिक तनाव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। उनके मुताबिक स्पोट्र्स तो स्पोट्र्स है। इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है। अगर इससे दोनों देशों के बीच थोड़े बहुत रिश्ते बेहतर हो सकते हैं तो इसमें बुराई नहीं है।

कोटक ने तैयारियों को लेकर कही यह बात

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच हमेशा की तरह हाई-वोल्टेज होने वाला है। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी खिलाड़ियों की तैयारी को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का पूरा ध्यान केवल क्रिकेट पर है और खिलाड़ी मैदान में केवल जीत हासिल करने की सोच के साथ उतरेंगे।

स्कूली ड्रेस के अन्दर बाबा साहब की टी शर्ट पहनकर स्कूल गए दलित छात्र की शिक्षकों ने की पिटाई,पीड़िता की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज

बहुजन समाज सहित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त

आरोपी शिक्षिका की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की कर रहे मांग।

(जीएनएस)।

सीतापुर। हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत खमीना गांव में एक दलित छात्र स्कूली ड्रेस के अंदर बाबा साहब की फोटो छपी टी-शर्ट पहनकर स्कूल चला गया जहां पर शिक्षिका द्वारा जातीय द्वेश भावना के चलते उस बच्चे की टी शर्ट फाड़ दी गई और मारा पीटा गया और 2 घंटे तक स्कूल में बंधक बनाए रखा गया।परिजनों द्वारा जानकारी होने पर स्कूल से बच्चे को छुड़ाया गया। उक्त दलित बच्चा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में कक्षा 8 का छात्र है।उक्त घटना की तहरीर परिजनों ने थाने में दी जिसके बाद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने में हीला हवाली की गई तब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए रात में ही अंबेडकर पार्क सीतापुर में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर सांकेतिक धरना देकर कार्रवाई की मांग की थी।जिसके क्रम में उक्त आरोपी शिक्षिका के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई लेकिन आरोपी शिक्षिका की गिरफ्तारी और उसकी बर्खास्तगी अभी तक नहीं की गई है जिससे समूचे बहुजन समाज सहित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हैं। कार्रवाई न होने के चलते गुस्साये कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने गांव के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार सदर सीतापुर को ज्ञापन देकर आरोपी शिक्षिका की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है।

वही आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विश्वदीप चौधरी ने बताया कि यदि सोमवार तक आरोपी शिक्षिका की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं की गई तो आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी सैकड़ों कार्यकताओं एवं ग्रामवासियों के साथ बड़ा आंदोलन करने को विवश होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी , जिला प्रभारी मोहनलाल ,विधिक सलाहकार एडवोकेट अरुण कुमार राज, जिला सलाहकार बृजेश कुमार जिला प्रभारी महोली सुपेंद्र सिंह आजाद, पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज चौधरी लीगल सेल जिला अध्यक्ष वीरेंद्र विक्रम, प्रेम वर्मा ,अरुण बॉस,विश्वपाल भारती भीम आर्मी जिला संयोजक राकेश राजवंशी,सरोज कुमार सुनील राठौर, विनोद भारती अनुपम गौतम,कमाल खान तथा सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे।

यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से आज लखनऊ में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री बोनी कपूर जी ने शिष्टाचार भेंट की।

सीएम श्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन किया

सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी आज जनपद लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन किया। साथ ही, नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण/शिलान्यास एवं चिकित्सा-शिक्षा, रोगी सेवा, अनुसंधान व प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 'दर टॉप-3 चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है। यह दिखाता है कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नगर आयुक्त ने मेडीकल किट बांटी

दैनिक सामग्री भी की वितरित, लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना

मथुरा (जीएनएस)। नगर निगम मथुरा-वृंदावन प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लक्ष्मीनगर, तिवारीपुरम कॉलोनी और जयसिंहपुरा खादर में संचारी रोगों से बचाव तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राहत सामग्री के साथ ही मेडिकल किट का भी वितरण किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर वितरण के दौरान नगर आयुक्त जग प्रवेश के साथ पार्षद श्रीमती रेनु चौधरी, यतेंद्र माहौर, कैबिनेट पार्षद राकेश भाटिया, मुन्ना मलिक, पार्षद प्रतिनिधि तिलकवीर चौधरी, रविकांत और बीएसए डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डा. ललित मोहन शर्मा मौजूद रहे। इस संबंध में नगर आयुक्त जग प्रवेश ने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, टूथपेस्ट, मच्छर भगाने की अगरबत्ती, सेवलोन, डिटोल, बोरोलीन, माचिस, मोमबत्ती, हेयर ऑयल और शैम्पू समेत मेडिकल किट (बैंडेज, एंटीबायोटिक, एंटी-एलर्जिक, पेनकिलर तथा मल्टीविटामिन) की किट दी गई। इस दौरान नगर आयुक्त ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से वार्ता करके उनका हाल-चाल जाना और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। नगर आयुक्त ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर सफाई कार्य, एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग अभियान लगातार चलाया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी तथा संचारी रोग को फैलने से रोका जा सके।

झाँसी में इंस्पेक्टर के तबादले पर सियासी बवाल, बीजेपी के दो विधायक आमने-सामने

झाँसी में एक इंस्पेक्टर के तबादले को लेकर बीजेपी के दो विधायकों के बीच चल रहा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पूरा मामला इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह के तबादले से जुड़ा है। बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य से शिकायत की, जिन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर के तबादले की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप इंस्पेक्टर का तबादला हो गया।

इसी बीच, झाँसी सदर विधायक रवि शर्मा ने मंत्री बेबी रानी मौर्य को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह का समर्थन किया। उन्होंने अपने पत्र में इंस्पेक्टर को 'मृदु व्यवहार' वाला और अपने काम के प्रति समर्पित बताया। यह पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया, जिससे बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आ गई।

फिलहाल, इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह के खिलाफ आरोपों की जाँच चल रही है, और इस मामले ने झाँसी की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। यह 'चिट्ठी-युद्ध' स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे एक छोटे से प्रशासनिक मुद्दे पर भी बड़े नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं।

लोक अदालत में बंदियों की बनायी सामग्री को न्यायिक अधिकारी के साथ लोगों ने जमकर खरीदा

: कारागार अधीक्षक के प्रयास ला रहे रंग, बंदी हो रहे स्वरोजगार में दक्ष

मथुरा (जीएनएस)। जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास सार्थक हो रहे हैं। कारागार अधीक्षक अंशुमन गर्ग के प्रयासों से बंदी स्वरोजगार के लिए दक्ष हो रहे हैं। शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हुई लोक अदालत में बंदियों द्वारा बनाए गए सामान को देखकर न्यायधीश और आए हुए लोग भी दंग रह गए। जानकारी के अनुसार शनिवार को न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा निर्मित सामान की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में कारागार के बंदियों द्वारा निर्मित हथकरघा की सूती साड़ियां, तौलिए, अंगोछा, रुई से बनाई गई बत्तियां, भगवान जी की पोशाक और मुकुट आदि प्रदर्शनी में लगाए गई। प्रदर्शनी में रखी गई सामग्री को न्यायिक अधिकारी और जनता के लोगों ने बेहद पसंद किया। इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन जिला जज विकास कुमार समेत अन्य न्यायिक अधिकारियो द्वारा किया गया। जिला न्यायधीश समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा बंदियों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को पसंद करते हुए खरीदा गया तथा कारागार प्रशासन के इस कार्य की जमकर सराहना की। इस मौके पर जिला जज ने कारागार अधीक्षक अंशुमन गर्ग के द्वारा कराए जा कार्यों को और अधिक व्यापक स्तर पर कराने का निर्देश दिए

सुरीर पुलिस ने दबोचा शातिर चोर : लाखों के जेवरात और नगदी बरामद

मथुरा (जीएनएस)। थाना सुरीर क्षेत्र स्थित अलीगढ़ रोड़ पर परसोती गढ़ी के पास से पुलिस ने मकान में घुसकर लाखों की चोरी करने वाले शातिर चोर को दबोच लिया। पकड़े गए शातिर के कब्जे से लाखों के जेवरात बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी सुरीर अभय शर्मा और एसआई नितिन तेवतिया पुलिस टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में जुटे हुए थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि मकान में घुसकर लाखों की चोरी करने वाला शातिर चोर, अलीगढ़ रोड़ पर परसोती गढ़ी के पास माइनर किनारे खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अभय शर्मा और एसआई नितिन तेवतिया पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को देखते ही शातिर चोर भागने लगा। पुलिस ने भागने का प्रयास कर रहे मानवेन्द्र उर्फ बड्डू पुत्र राजेन्द्र निवासी राजागढ़ी थाना सुरीर को घेराबंदी करके दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए शातिर चोर के कब्जे से चोरी की 4 सोने की चूड़ी पीली, 1 सोने का टीका, 1 सोने की बिंदी, 1 सोने की अंगूठी, 1 सोने की नथुनी, 1 चांदी का पैंडल, 14 चांदी के बिछुवा, 2 चांदी के सिक्के, 1 चांदी की कौंधनी, 1 चांदी का कमर गुच्छा, 2 चांदी की नथ, 1 चांदी का दीपक, 6 चांदी की पाजेब और नगदी समेत अन्य सामान बरामद किया है। पकड़े गए शातिर चोर ने विगत 24 जून को पीड़ित गिरीश कुमार पुत्र माधव मदन निवासी गांव इरौली जुन्नारदार थाना सुरीर के घर में घुसकर नगदी और जेवरात चोरी करके फरार हो गया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

बांकेबिहारी मंदिर में बदली दर्शन व्यवस्था : वीआईपी दर्शन पहले की तरह पूरे प्रोटोकॉल के तहत होंगे

-रैलिंग में लाइन लगाकर होंगे दर्शन, मंदिर का हाई पावर कमेटी ने किया स्थलीय निरीक्षण

मथुरा (जीएनएस)। ठाकुर श्री बांकेबिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने एक बार फिर मंदिर दर्शन व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है। अब नए आदेश के अनुसार मंदिर में प्रवेश, गेट नंबर 2 और 3 नंबर से लाइन लगाकर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब एक के पीछे एक श्रद्धालु दर्शन की कतार में नजर आएंगे। इसी के साथ निकासी की व्यवस्था गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से होगी। इसी के साथ कोई भी श्रद्धालु मंदिर में रुक नहीं सकेगा। दर्शन के बाद उसे जल्द निकलना होगा, इसके लिए रैलिंग लगाई जाएगी। इससे आगे वाले श्रद्धालु दर्शन करके ठाकुर जी के सामने से हटेगा तो फिर उसके पीछे कतार में खड़े श्रद्धालु को दर्शन का मौका मिल सकेगा। हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने वीआईपी दर्शन के बारे में कहा कि वीआईपी दर्शन पूर्व की तरह पूरे प्रोटोकॉल के तहत चलते रहेंगे, केवल गोस्वामियों द्वारा चलायी जा रही वीआईपी पर्ची की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। कहा कि मंदिर में बंद कमरा आने वाले समय में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक समिति द्वारा जो भी मंदिर की व्यवस्थाओं के संबंध में निर्णय लिए गए हैं, उनसे आम श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बताया कि सेवायतों के साथ आने वाले छुटभैया का आगमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। शनिवार को ठाकुर श्री बांकेबिहारी मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी अचानक वृंदावन पहुंच गई। वहां कमेटी ने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं देखीं। कई कमियां दिखने पर कमेटी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ठाकुर श्री बांकेबिहारी मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक मंदिर प्रांगण में हुई। इसकी जानकारी देते हुए कमेटी के अध्यक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि इससे पहले 11 सितंबर को बैठक हुई थी। इसमें लिए गए फैसलों पर अमल होने लगा है तथा यह तीसरी बैठक है। इसके बाद आज मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया गया तो कुछ कमियां मिली हैं। बताया कि कमेटी ने फैसला लिया है कि मंदिर में प्रवेश, गेट नंबर 2 और 3 से कतार में किया जाएगा। दर्शन के लिए तीन लाइन चलेंगी तथा निकासी भी इसी तरह होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि पुरुषों की लाइन में महिलाएं और महिलाओं की लाइन में पुरुषों दिखते हैं, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। कमेटी के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि गोस्वामियों के सहयोग से मंदिर में अनाधिकृत लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। सेवायत यह जानकारी देंगे कि उनके साथ सहयोगी के रूप में कौन-कौन मौजूद है, इसके बाद बाकी को बाहर किया जाएगा। बताते चलें कि बांकेबिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर श्री बांकेबिहारी जी मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी वृंदावन का गठन किया है। इसमें अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार बनाए गए हैं। इसके साथ ही कमेटी के सदस्य सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा, सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा विकास कुमार, सदस्य / मुंसिफ / सिविल जज मथुरा शिप्रा दुबे, डीएम चन्द्र प्रकाश सिंह को सचिव, सदस्य एसएसपी श्लोक कुमार, सदस्य नगर आयुक्त जग प्रवेश तथा सदस्य / एमवीडीए उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह के साथ मंदिर की राजभोग और शयन सेवा के दो-दो सेवायतों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पत्रकारों को जानकारी देने के दौरान सेवायतों में राजभोग सेवा के श्रीवर्धन गोस्वामी और शैलेन्द्र गोस्वामी तथा शयन सेवा से दिनेश कुमार और विजय कृष्ण गोस्वामी मौजूद रहे।

बल्देव पुलिस ने दो लुटेरों को दबोचा : लूटी गई नगदी और चोरी की बाइक बरामद

मथुरा (जीएनएस)। थाना बल्देव क्षेत्र स्थित नगला रतिया रोड़ से पुलिस ने लूट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शातिरों के कब्जे से लूटी गई नगदी और चोरी की बाइक बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित गिरांज सिंह पुत्र राम खिलाड़ी निवासी गांव नगला रतिया थाना महावन के साथ स्पलेंडर बाइक सवार 2 बदमाशों ने पीड़ित की मोपेड (विक्की) को ओवरटेक करके 55 हजार रूपए, पीड़ित की पत्नी श्रीमती भूरी देवी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक को लूटकर फरार हो गए थे। घटना का खुलासा करने और लुटेरों को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी बल्देव रंजना सचान पुलिस टीम के साथ जुटी हुई थीं। उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे नगला रतिया रोड़ की ओर जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रंजना सचान पुलिस टीम में एसआई वीरेन्द्र सिंह धामा, एसआई नितिन राठी, एसआई विनीत कुमार, मुख्य आरक्षी कैलाश चन्द्र, रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ वहां पहुंच गईं। उसी दौरान वहां होकर जा रहे बदमाशों को पुलिस टीम ने घेर लिया। पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास कर रहे शातिर बदमाश शिवा उर्फ शिवम पुत्र राजकुमार और मोहित पुत्र महेन्द्र निवासीगण नगला राय सिंह थाना महावन को घेराबंदी करके दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए शातिरों के कब्जे से लूटे गए 53 हजार रूपए, एक चोरी की बाइक, एक आधार कार्ड और एक एसबीआई की चेकबुक बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर हालचाल जाना सपा पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल

निघासन-खीरी।

समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल ने कार्यकर्ताओं संग विधानसभा क्षेत्र निघासन के बाढ़ प्रभावित आधा दर्जन गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों की शीघ्र सहायता किये जाने के साथ-साथ फसलों का उचित मुआवजा दिये जाने की मांग की है।

मंगलवार को सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल ने निघासन की बाढ़ प्रभावित ग्राम सभा लालपुर का दौरा किया। ग्रामसभा के मजरा लोनियन पुरवा, चंदन पुरवा, लालपुर, मंझली पुरवा तथा टापर पुरवा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के साथ हीला हवाली का आरोप लगाते हुये शीघ्र मदद किये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ के स्थाई समाधान के लिये प्रयास करना नहीं चाहती। हर साल किसानों की खून पसीने की कमाई बाढ़ के पानी में बह जाती है। वहीं दर्जनों जानें चली जाती हैं। नदियों की सफाई व नालों के चौड़ीकरण के नाम पर करोड़ो.की धनराशि बंदरबांट कर ली जाती है।

कोसीकलां पुलिस ने पकड़ा एक तस्कर : भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद

मथुरा (जीएनएस)। थाना कोसीकलां क्षेत्र स्थित कोटवन बॉर्डर के पास से पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कोसीकलां अरविंद निर्वाल और चौकी प्रभारी कोटवन अरविंद पूनियां पुलिस टीम के साथ संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि पलवल की ओर से बाइक सवार तस्कर अवैध शराब लेकर आ रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद निर्वाल और चौकी प्रभारी अरविंद पूनियां पुलिस टीम के साथ कोटवन बैरियर पहुंच गए और सघन चेकिंग शुरू कर दी। उसी दौरान बाइक पर सवार होकर आ रहे शराब तस्कर आले जॉनी पुत्र राजकुमार निवासी भातु कॉलोनी थाना कोसीकलां को घेरकर पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के कब्जे से हरियाणा निर्मित अवैध देशी शराब की 6 पेटी बरामद की हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

विधायक अनिल कुमार वर्मा ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा

(जीएनएस)।

जनपद सीतापुर।

विकास खण्ड बेहटा क्षेत्र में शारदा नदी के कटान से प्रभावित लखनीपुर गांव में शनिवार को क्षेत्रीय विधायक अनिल वर्मा ने दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की चिंताओं को समझा। विधायक ने मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कटान रोकने के लिए किए जा रहे बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और गांव को कटान से सुरक्षित करने के लिए स्थाई समाधान लागू करने के निर्देश दिए। गांव की महिलाओं ने विधायक अनिल वर्मा के सामने अपनी परेशानियां रखीं, जिसमें नदी के कटान से घरों और खेतों को होने वाला नुकसान प्रमुख था। ग्रामीणों ने नदी के किनारे सुरक्षा के लिए मजबूत उपायों की मांग की।

विधायक अनिल वर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कटान रोकने के कार्यों को तेज करने और गांव की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थाई समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में कटान की समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल सके। इस अवसर पर अतुल वर्मा, पद्दंपाल चौधरी सदस्य जिला पंचायत, प्रहलाद कन्नौजिया प्रतिनिधि सदस्य जिला पंचायत, उरूज अहमद,शेख रिजवान अतीक, जावेद खान, जावेद नसीर, मो. आलम, ग्राम प्रधान नबी अहमद सहित कई अन्य ग्रामीण और स्थानीय नेता मौजूद रहे।